यदि आप एक बार गिरकर हार मान लेते हैं तो आप अपने जीवन में कभी सफलता हासिल नहीं कर सकते।
अज्ञात।

विचार-प्रवाह देहरादून, बृहस्पतिवार, 24 फरवरी 2022

पेज थ्री
www.page3news.in

राजनीतिक मुद्दा बनाने की भी कोशिश

ध्यान रहे, अयोध्या में राममंदिर के निर्माण के लिए देश और समाज का बहुत कुछ दांव पर लगा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जब अयोध्या में मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हुआ, तो देश–विदेश में फैले करोड़ों हिंदू श्रद्धालुओं ने इसे अपनी आस्था की जीत माना था।

राधा शर्मा।।

अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कुछ रसूखदार लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर मंदिर परिसर के आसपास की जमीनें खरीदे जाने की खबरें परेशान करने वाली हैं। अच्छा है कि प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अविलंब इस मामले में जांच का आदेश दे दिया है। राजस्व विभाग के स्पेशल सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी द्वारा की जाने वाली इस जांच की रिपोर्ट एक सप्ताह में आने वाली है। स्वाभाविक ही, सबकी नजर अब इस बात पर टिकी है कि यह रिपोर्ट क्या कहती है।

वैसे एक अंग्रेजी अखबार में राममंदिर के पांच किलोमीटर के दायरे में जमीन खरीदे जाने की यह खबर छपते ही विपक्ष ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया जताई। उत्तर प्रदेश में चुनाव करीब हैं, इसलिए इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने की भी कोशिश होगी। अगर इस मुद्दे पर सियासत की बात रहने दें तो अयोध्या में रामजन्मभूमि मंदिर देश–विदेश के करोड़ों हिंदुओं के लिए आस्था से जुड़ा एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। ऐसे में मंदिर के आसपास स्थित जमीन के मालिकों से येन–केन प्रकारेण जमीन का मालिकाना हासिल कर लेने की प्रवृत्ति के पीछे और कुछ नहीं, कमाई बढ़ाने की भावना है।

सबसे बड़ी बात यह कि इसमें सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी के विधायक, मेयर और महत्वपूर्ण प्रशासनिक अधिकारियों के परिवारजनों के नाम आ रहे हैं। यानी पहली नजर में मामला सत्ताधारी पार्टी और प्रशानिक अधिकारियों की मिलीभगत से आम लोगों को औने–पौने दाम पर अपनी जमीन बेचने के लिए मजबूर करने का लगता है, जिसका मकसद बाद में उस जमीन से मोटी कमाई करना होगा।

ध्यान रहे, अयोध्या में राममंदिर के निर्माण के लिए देश और समाज का बहुत कुछ दांव पर लगा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जब अयोध्या में मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हुआ, तो देश–विदेश में फैले करोड़ों हिंदू श्रद्धालुओं ने इसे अपनी आस्था की जीत माना था। उसके बाद बड़ी संख्या में लोगों ने मंदिर निर्माण के लिए चंदा भी दिया है।

इस बीच, सरकार से जुड़े लोगों के अनियमितता करके जमीन खरीदने की खबर सामने आने से उन श्रद्धालुओं की भावनाओं को भी ठेस पहुंची होगी। इस मामले में मुख्यमंत्री ने जांच का आदेश देने में जिस तरह की तत्परता दिखाई है, वह निश्चित रूप से तारीफ के काबिल है। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है यह सुनिश्चित करना कि जांच सिर्फ दिखावे की कार्रवाई साबित ना हो। इसका तय समय के भीतर पूरा होना तो आवश्यक है ही, विश्वसनीय और पारदर्शी बने रहना भी जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, जांच में जो लोग भी दोषी पाए जाएं, उनके खिलाफ कानून के मुताबिक ऐसी ठोस कार्रवाई होनी चाहिए जो भविष्य में एक नजीर बने।

धर्मशास्त्र

धर्म-दर्शन

अशोक वोहरा। धर्मशास्त्र संस्कृत ग्रन्थों का एक वर्ग है, जो कि शास्त्र का ही एक प्रकार है। इसमें सभी स्मृतियाँ सम्मिलित हैं। यह वह शास्त्र है जो हिन्दुओं के धर्म का ज्ञान सम्मिलित किये हुए हैं, धर्म शब्द में यहाँ पारंपरिक अर्थ में धर्म तथा साथ ही कानूनी कर्तव्य भी सम्मिलित हैं। धर्मशास्त्रों का बृहद् पाठ भारत की ब्राह्मण परंपरा का अंग है, तथा यह विद्वत्परंपरा की देन एवं एक विशद तंत्र है। इसके गहन न्यायशास्त्रीय विवेचन के कारण प्रारंभिक ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासकों द्वारा यह हिंदुओं के लिए कानून के रूप में माना गया थाख्2, तब से लेकर आज भी धर्मशास्त्र को हिन्दू विधिसंहिता के रूप में देखा जाता है। धर्मशास्त्र में उपस्थित रिलीजन व कानून के बीच जो अंतर किया जाता है।

संपादकीय

नया नहीं है यह ट्रेंड

सवाल यह है कि कानून के जरिए कूलिंग पीरियड क्यों नहीं तय किया जा रहा? सचाई यह है कि खुद राजनीतिक पार्टियां ऐसा नहीं चाहती हैं। खासतौर पर राष्ट्रीय पार्टियां जो केंद्रीय सत्ता की असीम धुरी होती हैं। इसकी वजह यह है कि जब प्रभावी लोग पार्टी में आ रहे होते हैं तो पार्टी नेताओं को यह अच्छा लगता है। तब उन्हें इसमें कोई नैतिक बुराई नजर नहीं आती। जो भी पार्टी सत्ता में होती है, उसके साथ प्रभावी लोगों के जुड़ने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। असीम अरुण न तो पहले शख्स हैं जिन्होंने वीआरएस लेकर राजनीति में एंट्री की और न ही उन्हें आखिरी कहा जा सकता है। ऐसा भी नहीं कि यह सिलसिला हाल–फिलहाल के वर्षों का है। यह बहुत पुराना ट्रेंड है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के यशवंत सिन्हा अपनी सेवा पूरी करने के 13 साल पहले ही 1984 में वीआरएस लेकर राजनीति में आ गए थे। उनकी गिनती चंद्रशेखर के विश्वासपात्र अफसरों में होती रही है। उन्हीं के भरोसे वह राजनीति में आए, सांसद हुए। इस वजह से उसके नेता अपनी पार्टी के लिए अवसर का दरवाजा खोले रखना चाहती हैं। उन्हें नैतिकता तभी याद आती है जब वे सत्ता से बाहर हो जाते हैं।

इसके बाद से ही एक बार फिर यह बहस शुरू हो गई कि राजनीति में जो इस तरह की 'वाइल्ड कार्ड' एंट्री होती हैं, वे कितनी नैतिकतापूर्ण होती हैं?

मांग तो काफी समय से हो रही है

नदीम।।

पांच राज्यों के चुनाव के मौके पर 'बजरिए' असीम अरुण नैतिकता की तलाश हो रही है। असीम अरुण यूपी के हैं। पुलिस कमिश्नर रहे हैं। उम्र के लिहाज से अभी वह नौ साल और नौकरी कर सकते थे। लेकिन जिस रोज चुनाव आयोग पांच राज्यों की चुनाव की तारीख का एलान कर कर रहा था, उसी रोज वह लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर वीआरएस के लिए अर्जी लगा रहे थे। उसी दिन यह मान लिया गया कि वह राजनीति की तरफ कदम बढ़ाने जा रहे हैं। फिर हुआ भी वही। पिछले रविवार उन्होंने बीजेपी जॉइन कर ली। अब वह चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बीजेपी ने यह कह कर इशारा भी दे दिया कि असीम ने दलित, पिछड़े, वंचित समाज के सम्मान के लिए काम किया है। इसके बाद से ही एक बार फिर यह बहस शुरू हो गई कि राजनीति में जो इस तरह की 'वाइल्ड कार्ड' एंट्री होती हैं, वे कितनी नैतिकतापूर्ण होती हैं?

सवाल उठ रहा है कि जो असीम अरुण बीजेपी के इतने नजदीक निकले, उन्होंने क्या सेवाकाल के दौरान बीजेपी को लाभ पहुंचाने की कोशिश नहीं की होगी? समाजवादी पार्टी तो बाकायदा चुनाव आयोग पहुंच गई है, यह मांग लेकर कि चूंकि असीम अरुण वरिष्ठ पदों पर रहे हैं, उनका अपने अधीनस्थ कर्मियों पर प्रभाव होना स्वाभाविक है। इस वजह से पिछले पांच वर्षों के दौरान उनके साथ जिन पुलिसकर्मियों ने भी काम किया है, उन्हें चुनाव ड्यूटी से अलग किया जाए। यह बहस भी जोर पकड़ने लगी है कि क्या किसी कानून के जरिए ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता कि नौकरीपेशा लोगों के वीआरएस लेकर या रिटायरमेंट के बाद राजनीति में आने का कोई 'कूलिंग पीरियड' तय हो, क्योंकि प्रभावी पदों पर बैठे लोगों के राजनीति में आने की महत्वाकांक्षा से उनकी निष्पक्षता के प्रभावित होने का खतरा बना रहता है।

'कूलिंग पीरियड' तय करने का कानून तो बन ही सकता है। खुद केंद्रीय निर्वाचन आयोग भी इसका हिमायती रहा है। समय–समय पर उसने चुनाव प्रक्रिया में सुधार के लिए जो सुझाव रखे हैं, उनमें एक सुझाव यह भी शामिल रहा है। वर्ष 2012 में बीजेपी के दिग्गज नेता, जो कि उस वक्त राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में थे, अरुण जेटली (अब स्वर्गीय) ने जजों के लिए भी 'कूलिंग पीरियड' तय करने की वकालत की थी। उन्होंने सदन में कहा था, 'सेवानिवृत्ति से पहले लिए गए फैसले सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले पद की चाहत में प्रभावित होते हैं। मेरी सलाह है कि सेवानिवृत्ति के बाद दो सालों का अंतराल होना चाहिए, अन्यथा सरकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अदालतों को प्रभावित कर सकती है और एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और ईमानदार न्यायपालिका कभी भी वास्तविकता नहीं बन पाएगी।'

केंद्र सरकार में अहम पदों पर रह चुके रिटायर्ड आईएएस योगेंद्र नारायण भी कई मौकों पर कह चुके हैं कि ब्यूरोक्रेट्स के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड जरूर रखा जाना चाहिए। कुछ समय पहले इस सवाल पर कि ब्यूरोक्रेट्स राजनीति में जाने के लिए खुद राजनीतिक दलों से संपर्क साधते हैं या राजनीतिक दलों की तरफ से पहल होती है, योगेंद्र नारायण ने बताया था जब कभी किसी ब्यूरोक्रेट को लगता है कि अमुक पार्टी की नीतियां उसके विचारों से मेल खाती हैं तो वह उसमें जाने के लिए पहल करता है।

सूडोकू नवताल- 5203

*****

7							4	
		5		3			7	
					8			2
					1	9		
	2						8	
		6	7					
1			4					
	9			2		5		
	8							1

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं।
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3x3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें।
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते।
- पहेली का केवल एक ही हल है।

सूडोकू नवताल -5202 का हल

8	4	5	6	1	3	7	2	9
7	2	6	4	9	5	3	8	1
9	3	1	7	8	2	6	5	4
1	7	2	9	6	8	4	3	5
5	6	9	3	2	4	1	7	8
4	8	3	5	7	1	9	6	2
2	9	7	1	5	6	8	4	3
3	1	8	2	4	7	5	9	6
6	5	4	8	3	9	2	1	7

अपना ब्लॉग

राज्यों के क्षेत्रीय दलों में भी ऐसे उदाहरण

मोहन। ऐसे ही जब कभी सरकार को लगता है कि अमुक ब्यूरोक्रेट किसी खास फील्ड का एक्सपर्ट है, उसे सरकार में शामिल करने से उसकी क्षमता का कहीं ज्यादा लाभ लिया जा सकता है तो वह उसे पॉलिटिक्स में आने का ऑफर देती है। योगेंद्र नारायण ने यह भी बताया कि 2009 के लोकसभा चुनाव में उन्हें बीजेपी और कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों की तरफ से चुनाव लड़ने का ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। जब चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला तो उनकी कैबिनेट में मंत्री भी हुए। नटवर सिंह भी भारतीय विदेश सेवा में हुआ करते थे। वह भी सेवा के सात साल पहले वीआरएस लेकर वर्ष 1984 में कांग्रेस से सांसद हुए थे। अलग–अलग राज्यों के क्षेत्रीय दलों में भी ऐसे उदाहरण देखने को मिल जाते हैं। वे जिस पार्टी के साथ भविष्य में जाना चाहते हैं, उसे 'खुश' करने का कोई मौका नहीं गंवाना चाहेंगे।